3 कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई

5 छात्र राजनीति से कांग्रेस पार्टी का प्रमुख चेहरा

7 श्रीगणेश से सीखिये- सुनना, चुनना, आगे बढ़ना

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 17 अंक : 17 | प्रति सोमवार, 14 सितंबर 2026 | मूल्य : दो रुपये | पृष्ठ : 8

राशन में घोटाले के आरोपों से घिरे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत

गरीब का राशन, मिलों की मौज, राजपूत के विभाग पर गंभीर सवाल

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

मध्यप्रदेश में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में राशन की दुकानों से जुड़ी कथित अनियमितताओं की शिकायतें सामने आने के बाद व्यवस्था की पारदर्शिता और निगरानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं घटिया गुणवत्ता का अनाज दिए जाने की बात सामने आ रही है तो कहीं खाद्यान्न में मिलावट की शिकायतें बताई जा रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस राशन की एक-एक बोरी गरीब परिवारों के लिए राहत का आधार होनी चाहिए, वह आखिर रास्ते में ही गुणवत्ता और वितरण की कसौटी पर कैसे कमजोर पड़ रही है? यदि किसी दुकान पर घटिया अनाज पहुंचता है, यदि खाद्यान्न की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है अथवा यदि अच्छे और खराब अनाज की अदला-बदली की जाती है, तो यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ा गंभीर विषय बन जाता है। विभागीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की उपयोगिता पर भी प्रश्नचिंह

हैं। प्रदेश के कई हिस्सों से सामने आ रही शिकायतों ने इस पूरी व्यवस्था की निगरानी को कठघरे में खड़ा किया है। सवाल यह है कि राशन गोदाम से लेकर परिवहन और फिर उचित मूल्य की दुकान तक पहुंचने के दौरान खाद्यान्न की गुणवत्ता की जांच किस स्तर पर होती है? यदि अनाज खराब है तो उसे राशन दुकानों तक पहुंचने की अनुमति किसने दी? और यदि दुकान संचालक स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो संबंधित विभागीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और विभागीय अधिकारियों ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की?

मंत्री राजपूत की भूमिका पर भी उठ रहे सवाल

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के संरक्षण में राशन का फर्जीवाड़ा चलने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस तरह के गंभीर आरोपों की पुष्टि किसी स्वतंत्र जांच के बिना नहीं की जा सकती। ऐसे में सरकार के सामने सबसे उचित रास्ता यही है कि आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी मानकर खारिज करने के बजाय पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि आरोप निराधार हैं तो जांच से स्थिति साफ हो जाएगी और यदि गड़बड़ी सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई का रास्ता खुलेगा। मंत्री के विधानसभा क्षेत्र से भी कथित अनियमितताओं की शिकायतें सामने आने का दावा किया जा रहा है। यदि ऐसा है तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि संबंधित क्षेत्र की राशन दुकानों, गोदामों और खाद्यान्न की आपूर्ति व्यवस्था का स्वतंत्र निरीक्षण कराया जाए। (शेष पेज 2 पर)

सशक्त बचपन और सुरक्षित भविष्य ही समृद्ध छत्तीसगढ़ की सबसे मजबूत नींव है

बच्चों के पोषण, संरक्षण, शिक्षा और सर्वांगीण विकास में साय सरकार के प्रयास

-विजया पाठक

किसी भी समाज और प्रदेश की समृद्धि का वास्तविक आकलन केवल आर्थिक विकास के आंकड़ों से नहीं किया जा सकता। किसी राज्य का भविष्य उसकी आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और संस्कारों में दिखाई देता है। इसी सोच को केंद्र में रखते हुए छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने बच्चों और महिलाओं के कल्याण को विकास की प्राथमिकताओं से जोड़ा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के सक्रिय नेतृत्व में पोषण, बाल संरक्षण, आंगनबाड़ी सेवाओं के विस्तार, बाल विवाह की रोकथाम और जरूरतमंद बच्चों के पुनर्वास के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण पहलें आगे बढ़ी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों का केंद्र केवल कुपोषण को कम करना नहीं, बल्कि बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहां उसे पोषण के साथ शिक्षा, सुरक्षा, खेल, संस्कार और आगे बढ़ने के अवसर मिल सकें। इसी व्यापक दृष्टिकोण का परिणाम है कि पोषण पखवाड़ा और पोषण माह की गतिविधियों में प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है।

आधुनिक बन रहे आंगनबाड़ी केंद्र

बच्चों के विकास की पहली संस्थागत सीढ़ी आंगनबाड़ी केंद्र हैं। सरकार ने इन केंद्रों को केवल पोषण वितरण के स्थान के रूप में नहीं, बल्कि बाल विकास के आधुनिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। प्रदेश में 11 हजार 490 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम और आकर्षक बनाने का कार्य जारी है। इन केंद्रों में बिल्डिंग एज लर्निंग एड यानी पेंटिंग, पोषण वाटिका, खेल और शिक्षण आधारित गतिविधियों जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। (शेष पेज 2 पर)

कमलनाथ ने दी थी राजधानी को बेहतर मास्टर प्लान की योजना

मास्टर प्लान रुका, भोपाल के विकास की रफ्तार भी थमी

-विजया पाठक

भोपाल जैसे तेजी से विस्तार करते शहर के लिए मास्टर प्लान महज एक सरकारी दस्तावेज नहीं, बल्कि आने वाले दशकों के विकास की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण रोडमैप है। सड़कें कहां बनेंगी, बाजार किस क्षेत्र में विकसित होंगे, आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों का स्वरूप क्या होगा, यातायात का दबाव कैसे नियंत्रित किया जाएगा और शहर का विस्तार किस दिशा में होगा, इन सभी सवालों का जवाब एक प्रभावी मास्टर प्लान में छिपा होता है। लेकिन राजधानी भोपाल में यही मास्टर प्लान लंबे समय से इंतजार का विषय बना हुआ है। नया मास्टर प्लान कब लागू होगा, इसकी स्पष्टता अब भी जनता के सामने नहीं है। दूसरी ओर, 15 सितंबर की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आती जा रही है, व्यापारियों और आम नागरिकों की चिंता बढ़ती जा रही है। वर्षों से चल रहे कारोबार पर सीलबंदी और तालेबंदी की आशंका ने राजधानी के व्यापारिक वर्ग के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। सवाल सीधा है जब शहर वर्षों से बिना नये मास्टर प्लान के विस्तार करता रहा, तब प्रशासन ने समय रहते इसकी जरूरत क्यों नहीं समझी? और यदि शहर की मौजूदा वास्तविकता पुराने नियमों से अलग हो चुकी है, तो उसका समाधान केवल कार्रवाई और सीलबंदी ही क्यों माना जा रहा है?

कमलनाथ की सोच में था भविष्य का भोपाल

भोपाल के मास्टर प्लान पर चर्चा करते समय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यकाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कमलनाथ लंबे समय से शहरी नियोजन, औद्योगिक विकास और अधोसंरचना को एक-दूसरे से जोड़कर देखने की सोच के लिए जाने जाते हैं। (शेष पेज 3 पर)

सशक्त बचपन और सुरक्षित भविष्य ही समृद्ध छत्तीसगढ़ की सबसे मजबूत नींव है

(पेज 1 का शेष)

मनरेगा अभिसरण के माध्यम से 2 हजार 337 नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 191 नए आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो चुके हैं। वहीं नियद नेल्ला नार 2.0 के तहत 10 जिलों में 12 हजार 964 आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों तक सेवाएं पहुंचा रहे हैं। यह विस्तार बताता है कि सरकार दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों के बच्चों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। आंगनबाड़ी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मानव संसाधन पर भी ध्यान दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या 51 हजार 45 से बढ़कर 52 हजार 258 तथा सहायिकाओं की संख्या 44 हजार 826 से बढ़कर 51 हजार 548 हुई है। इससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक सेवाओं की पहुंच मजबूत हुई है।

कुपोषण के खिलाफ निर्णायक अभियान

बच्चों के स्वस्थ भविष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में कुपोषण प्रमुख है। छत्तीसगढ़ में पोषण ट्रैकर के आंकड़े इस दिशा में हुए सुधार की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में स्टंटिंग में 7.82 प्रतिशत, वेट में 4.36 प्रतिशत और अंडरवेट में 2.76 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। दिसंबर 2023 में बौनापन की दर जहां 30.27 प्रतिशत थी, वह जून 2026 तक घटकर 22.45 प्रतिशत रह गई। यह परिवर्तन केवल आंकड़ों में कमी नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव का संकेत है। नियमित निगरानी, पोषण प्रबंधन, आंगनबाड़ी आधारित सेवाओं और सामुदायिक सहभागिता ने इस अभियान को मजबूती दी है। पोषण अभियान में भी छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय रहा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रति आंगनबाड़ी गतिविधियों के मामले में प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। अप्रैल 2025 के पोषण पखवाड़े में भी छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया। सितंबर-अक्टूबर 2025 के पोषण माह में 71 हजार 887 गतिविधियां और अप्रैल 2026 के पोषण पखवाड़े में 34 लाख 93 हजार 474 गतिविधियां आयोजित की गईं। स्थानीय स्तर पर पौष्टिक आहार की उपलब्धता बढ़ाने के लिए रेडी टू ईट इकाइयों की स्थापना की दिशा में भी पहल की जा रही है।

संरक्षण की छतरी बनेगा मिशन वात्सल्य

हर बच्चे को परिवार और सुरक्षा का अधिकार है, लेकिन अनाथ, परित्यक्त तथा विशेष संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए यह अधिकार सुनिश्चित करना सरकार की विशेष जिम्मेदारी है। मिशन वात्सल्य के माध्यम से ऐसे बच्चों के लिए सुरक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था को मजबूत किया गया है। राज्य में बाल देखरेख संस्थाओं की संख्या बढ़कर 109 हो गई है। मुख्यमंत्री बाल उदय योजना के माध्यम से बच्चों को शिक्षा, देखभाल और पुनर्वास का सहारा मिला है। चाइल्ड हेल्पलाइन पर प्राप्त 1 लाख 65 हजार 979 कॉलों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हजारों मामलों का निराकरण किया गया। इससे स्पष्ट है कि बाल संरक्षण को केवल कागजी व्यवस्था न बनाकर जरूरतमंद बच्चों तक त्वरित सहायता पहुंचाने का प्रयास किया गया है। दत्तक ग्रहण और स्पॉन्सरशिप योजनाओं में भी वृद्धि इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दत्तक ग्रहण से लाभान्वित बच्चों की संख्या 42 से बढ़कर 234 और स्पॉन्सरशिप का लाभ पाने वाले बच्चों की संख्या 767 से बढ़कर 2 हजार 37 हो गई है। इन योजनाओं का उद्देश्य बच्चों को बेहतर पारिवारिक वातावरण, शिक्षा और सुरक्षित भविष्य उपलब्ध कराना है।

बाल विवाह के खिलाफ सामाजिक संकल्प

बच्चों की सुरक्षा केवल उन्हें कुपोषण से बचाने तक सीमित नहीं है। बाल विवाह भी उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य के लिए गंभीर चुनौती है। इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान को सामाजिक आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में काम किया है। बाल विवाह प्रतिरोध अधिकारियों की संख्या बढ़कर 1 हजार 382 हो गई है। इसके परिणामस्वरूप रोके गए बाल विवाहों की संख्या 109 से बढ़कर 888 तक पहुंची है। यह आंकड़ा बताता है कि प्रशासनिक सक्रियता के साथ समाज में जागरूकता भी बढ़ रही है। बाल विवाह रोकना केवल कानून का पालन कराना नहीं, बल्कि बेटियों को शिक्षा पूरी करने, आत्मनिर्भर बनने और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देना है।

महिलाओं के सशक्तीकरण से परिवार और समाज मजबूत

बच्चों के बेहतर भविष्य की नींव तभी मजबूत हो सकती है, जब परिवार और विशेष रूप से महिलाएं सुरक्षित, जागरूक और सशक्त हों। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को केंद्र में रखकर संचालित योजनाएं इसी व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा हैं। महिला की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता का सीधा प्रभाव बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके भविष्य पर पड़ता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकता ऐसी व्यवस्था विकसित करने की है, जिसमें महिला और बाल कल्याण योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की बढ़ती संख्या भी इसी व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूत करती है। गांव और दूरस्थ क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच में इन कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।

सशक्त बचपन ही विकसित छत्तीसगढ़ की पहचान

छत्तीसगढ़ में बच्चों के पोषण से लेकर उनके संरक्षण और बाल विवाह की रोकथाम तक किए जा रहे प्रयास एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक ओर आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर कुपोषण के आंकड़ों में सुधार के लिए लगातार निगरानी हो रही है। जरूरतमंद बच्चों के लिए मिशन वात्सल्य और मुख्यमंत्री बाल उदय योजना सुरक्षा का आधार बन रहे हैं, वहीं बाल विवाह के खिलाफ अभियान बेटियों के भविष्य की रक्षा कर रहा है। इन प्रयासों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनमें शासन, प्रशासन और समाज की सहभागिता को साथ लाने का प्रयास दिखाई देता है। पोषण पखवाड़े की करोड़ों गतिविधियां हों या बाल विवाह रोकने के लिए बढ़ती प्रशासनिक सक्रियता- इन अभियानों का लक्ष्य केवल सरकारी उपलब्धि दर्ज करना नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ जिस विकास की कल्पना कर रहा है, उसमें सशक्त बचपन और सुरक्षित मातृत्व-बचपन की भूमिका केंद्रीय है। स्वस्थ बच्चा आगे चलकर शिक्षित और सक्षम नागरिक बनता है तथा सशक्त महिला परिवार की सामाजिक और आर्थिक शक्ति को बढ़ाती है। इसलिए बच्चों का पोषण, उनका संरक्षण और महिलाओं का सशक्तीकरण किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की आधारशिला है।

छत्तीसगढ़ में दो लाख नवनिर्मित आवासों का गृह प्रवेश कराया

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. रायपुर। छत्तीसगढ़ में गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के पक्के आवास के सपने को साकार करने की दिशा में आज एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ा। सक्ती में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के राज्यस्तरीय गृह प्रवेश समारोह में 2 लाख नवनिर्मित आवासों का गृह प्रवेश कराया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से उनके नए घरों की चाबी सौंपी गई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री चौहान ने छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 3.65 लाख अतिरिक्त आवासों की बड़ी सौगात दी। उन्होंने नवगठित सक्ती जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने तथा बस्तर संभाग में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सर्वे की समय-सीमा 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाने की घोषणा भी की। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने अतिरिक्त आवासों की स्वीकृति संबंधी पत्र मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को सौंपा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं और ग्रामीण परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण इसी संकल्प को जमीन पर साकार करने वाली महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास निर्माण का कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है और प्रतिदिन 1600 से अधिक आवास पूर्ण किए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा विकास कार्यों की सराहना की। केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि सरकार जो कहती है, उसे पूरा करके दिखाती है।

राशन दुकानों की गड़बड़ियां उठाती हैं व्यवस्था की निगरानी पर गंभीर सवाल, करोड़ों हितग्राहियों के हक पर कौन डाल रहा है डाका?

(पेज 1 का शेष)

विपक्ष और सरकार दोनों की परीक्षा

राशन व्यवस्था का मुद्दा राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील है। विपक्ष के लिए यह सरकार को घेरने का मुद्दा हो सकता है, जबकि सरकार के लिए अपनी व्यवस्था की पारदर्शिता साबित करने की चुनौती। लेकिन इस पूरे विवाद का केंद्र राजनीति नहीं बल्कि गरीब परिवार का अधिकार होना चाहिए। सरकार को आरोपों का जवाब केवल बयान जारी करके नहीं, बल्कि जांच और कार्रवाई के जरिए देना चाहिए। यदि गड़बड़ी नहीं है तो जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाएं। यदि गड़बड़ी है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। इसी से जनता का विश्वास कायम होगा।

सवाल अभी बाकी हैं

मध्यप्रदेश की राशन व्यवस्था से जुड़े मौजूदा आरोप कई महत्वपूर्ण सवाल छोड़ते हैं। क्या राशन दुकानों तक पहुंचने वाले अनाज की नियमित गुणवत्ता जांच हो रही है? क्या गोदाम से निकलने वाले और हितग्राही को मिलने वाले अनाज की गुणवत्ता समान है? क्या शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई होती है? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होती है? इन सवालों के जवाब केवल कागजों में नहीं, जमीन पर दिखाई देने चाहिए। गरीबों के नाम पर चलने वाली किसी भी योजना में भ्रष्टाचार अथवा अनियमितता की गुंजाइश लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य गरीब की थाली तक सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण भोजन पहुंचाना है। यदि इसी रास्ते में कहीं खाद्यान्न की गुणवत्ता से समझौता हो रहा है, तो सरकार को इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर तत्काल जांच करनी चाहिए। आखिर जिस अनाज पर किसी गरीब परिवार की रसोई निर्भर है, उसकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी भी सरकार की ही है। गरीब के हिस्से का राशन अगर रास्ते में ही कमजोर पड़ गया, तो सवाल सिर्फ अनाज का नहीं, पूरी व्यवस्था की नीयत और निगरानी का बन जाता है।

गरीब की थाली से खिलवाड़ का असर

राशन की गुणवत्ता में गड़बड़ी का सबसे ज्यादा असर उन परिवारों पर पड़ता है जिनकी आर्थिक स्थिति पहले से कमजोर है। जिन परिवारों के लिए सरकारी राशन उनके घरेलू बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वे खराब अनाज मिलने पर उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। यही कारण है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गुणवत्ता से समझौता किसी सामान्य प्रशासनिक शिकायत की तरह नहीं देखा जा सकता। गरीब परिवारों को मिलने वाला खाद्यान्न यदि घटिया है, तो इसका असर उनके भोजन की गुणवत्ता पर पड़ता है। वहीं यदि मात्रा में कटौती अथवा मिलावट होती है तो सीमित संसाधनों में घर चलाने वाले परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है।

स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों एवं प्रतिभावान बालिका का सम्मान

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। शक्ति व्यायामशाला के कोच मुबारिक शाह ने बताया कि व्यायामशाला के तीन प्रतिभावान खिलाड़ियों आफताब शाह, पीयूष यादव एवं हर्ष नायर ने राजस्थान के जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय यूथ गेम्स नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व किया। खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मध्यप्रदेश टीम के साथ स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) प्राप्त कर क्षेत्र एवं संस्था का नाम गौरवान्वित किया। इन खिलाड़ियों की उल्लेखनीय उपलब्धि पर शक्ति व्यायामशाला संस्था द्वारा तीनों खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। इसी अवसर पर टिमरनी की दो वर्ष नौ माह की बालिका हन्वीका कनाठे का भी सम्मान किया गया। हन्वीका ने मात्र 44 सेकंड में भारत के सभी राज्यों की राजधानियों को अंग्रेजी वर्णमाला (Alphabetical) क्रम में बताकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्यजनों ने खिलाड़ियों एवं बालिका की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर व्यायामशाला से रमेश तिवारी अध्यक्ष शक्ति वर्य शाला टिमरनी राजेंद्र नागरे, वकील साहब, साबिर शाह, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टिमरनी के शिक्षक मुकेश तिवारी एवं कोच मुबारिक शाह, शासकीय महाविद्यालय टिमरनी के व्यायाम शिक्षक नीतेश कनाठे, शैलेन्द्र राजपूत, दीपक बिवरिया, प्रमिला चावरे, राजनंदिनी धनोरे, निकहत शाह, पूजा कनाटे विशाखा फरहत शाह आदि उपस्थित रहे।

कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. सागर। कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर आबकारी विभाग की टीम ने बंडा और बाछलोन क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 10.3 लाख रुपये मूल्य की मदिरा बरामद की है। पहली कार्रवाई 10 सितंबर की देर रात बंडा क्षेत्र के ग्राम हीरापुर (थाना शाहगढ़) में की गई। मुखबिर की सूचना पर आबकारी अमले ने फरार आरोपी मनीष लोधी द्वारा शराब के बड़े ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे मकान पर छापा मारा। तलाशी के दौरान विभिन्न विदेशी मदिरा ब्रांड की 261 बल्क लीटर शराब बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 2.8 लाख है। आरोपी के खिलाफ म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क, 34(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दूसरी कार्रवाई 11 सितंबर को वृत्त आंतरिक क्षेत्र के ग्राम बाछलोन में की गई। यहाँ एक खाली मकान की तलाशी लेने पर 96 पेटी विदेशी मदिरा, बीयर और देशी मदिरा (कुल 164 बल्क लीटर) जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 7.5 लाख आंकी गई है।

खाद की असुविधा से किसान परेशान

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। किसानों को खाद के लिए काफी परेशान होना पड़ रहा है। धान और मक्का के लिए किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। समय पर खाद न मिलने के कारण पहले एक किसान के खातेदार 10 लोग हैं। बहन-भाई के नाम है अब किसान को खाद लेना है तो सभी के ओटीपी लगते हैं। यदि बहन दूर है तो उनसे ओटीपी लेने में असुविधा दोनों को होती है। दूसरा जो किसान खेती कर रहा है उस व्यक्ति के नाम पर खाद मिलना चाहिए।

बंडा जहरीली शराबकांड: पुलिस-आबकारी की संयुक्त छापामार कार्रवाई

-संदीप सबलोक

जगत प्रवाह. सागर। बंडा क्षेत्र में हुए जहरीली शराब प्रकरण के बाद जिला प्रशासन और पुलिस सख्त मोड में आ गई है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देश पर आबकारी विभाग और सागर पुलिस की संयुक्त टीम ने शाहगढ़ थाना क्षेत्र की हीरापुर चौकी अंतर्गत ग्राम हीरापुर में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने एक मकान में चल रहे अवैध शराब के गोदाम का पर्दाफाश करते हुए 2.80 लाख रुपये मूल्य की 261 बल्क लीटर अवैध विदेशी मदिरा बरामद की है। **ओल्ड मॉंक, ब्लेंडर्स प्राइड और रॉयल स्टैग सहित कई ब्रांड्स बरामद**

मकान की तलाशी के दौरान भारी मात्रा में नामी ब्रांड्स की अंग्रेजी/विदेशी मदिरा की पेटियां बरामद की गईं। जब्त की गई शराब में ओल्ड मॉंक व्हिस्की, लंदन प्राइड बोदका, ब्लेंडर्स प्राइड व्हिस्की, गोवा रम, व्हाइट मिश्चिफ, रॉयल सिलेक्ट, फॉक्स ऑरेंज, 8 पीएम, महावत, रॉयल स्टैग, ग्रीन लेबल व्हिस्की एवं ब्लैक फोर्ट रम सहित अन्य महंगी ब्रांड्स शामिल हैं। मौके से कुल 261 बल्क लीटर अवैध विदेशी मदिरा जब्त की गई, जिसकी बाजार कीमत लगभग 2,80,000 आंकी गई है।

आखिर भोपाल की जनता को कब मिलेगा नया मास्टर प्लान?

(पेज 1 का शेष)

उनके समर्थकों का तर्क है कि यदि उनकी सरकार का प्रस्तावित दृष्टिकोण और शहरी नियोजन की दिशा आगे बढ़ती, तो भोपाल को आज की तरह अनिश्चितता के दौर से नहीं गुजरना पड़ता। कमलनाथ की सबसे बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक पहचान छिंदवाड़ा के विकास मॉडल से जोड़ी जाती है। जिस तरह छिंदवाड़ा में सड़क, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी सुविधाओं को एक व्यापक विकास दृष्टि से जोड़ने की कोशिश की गई, उसी सोच को भोपाल जैसे बड़े शहर में लागू करने की आवश्यकता थी। यही कारण है कि मास्टर प्लान को केवल जमीन के उपयोग का नक्शा मानने के बजाय उसे शहर की आर्थिक और सामाजिक जरूरतों से जोड़कर देखने की जरूरत है।

कमलनाथ मॉडल की जरूरत क्यों महसूस हो रही है?

कमलनाथ के समर्थक यह सवाल उठा रहे हैं कि यदि उनके समय में भोपाल के लिए प्रस्तावित शहरी नियोजन को आगे बढ़ाया गया होता, तो क्या आज की स्थिति पैदा होती? इसका निश्चित उत्तर राजनीतिक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि किसी भी सरकार के लिए दीर्घकालिक शहरी योजना को समय पर लागू करना प्राथमिकता होनी चाहिए। भोपाल आज जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए पुराने नियमों के आधार पर नये शहर का निर्माण संभव नहीं है। राजधानी में आबादी बढ़ रही है, वाहन बढ़ रहे हैं, व्यापार बढ़ रहा है और नई कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। ऐसे में मास्टर प्लान जितना देर से लागू होगा, जमीन पर उतनी ही ज्यादा जटिलताएं पैदा होंगी। यही वह जगह है जहां कमलनाथ की शहरी विकास की सोच को राजनीतिक

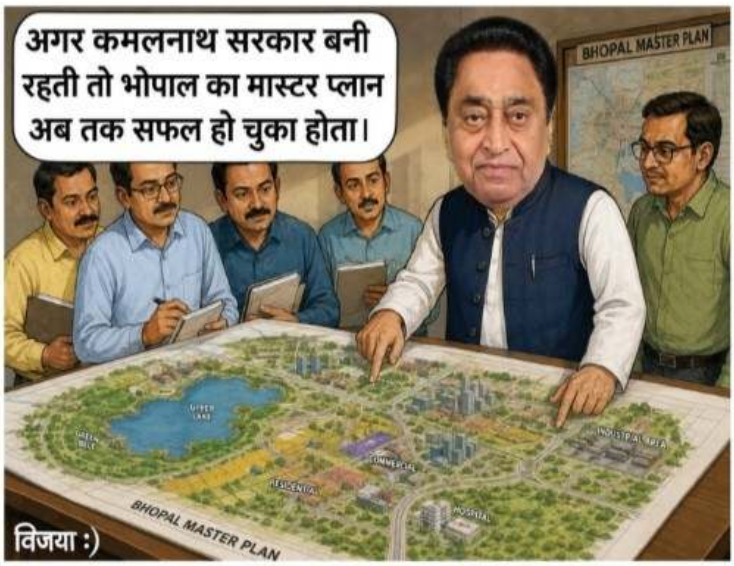

विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। एक ऐसी सोच, जिसमें विकास को केवल निर्माण कार्य नहीं बल्कि समग्र शहरी नियोजन के रूप में देखा जाए।

देश ने देखा है छिंदवाड़ा का विकास

कमलनाथ ने जिस तरह छिंदवाड़ा के विकास को व्यापक दृष्टि से देखा, उसी तरह की सोच भोपाल को भी चाहिए। भोपाल को ऐसा अर्बन प्लानर चाहिए जो केवल नक्शे पर लाइनें खींचने के बजाय शहर की धड़कन समझे। अब जरूरत है कि सरकार अपनी 'कुंडी' खोले, जनता और व्यापारियों के बीच आए और स्पष्ट रोडमैप सामने रखे। क्योंकि मास्टर प्लान विकास की सीढ़ी होना चाहिए, जनता की आजीविका पर लटकती तलवार नहीं। और भोपाल अब यह सवाल पूछने के लिए मजबूर है आखिर नया मास्टर प्लान कब आएगा?

गलती जनता की या सिस्टम की?

यदि कोई व्यक्ति वर्षों से एक दुकान चला रहा है, टैक्स दे रहा है, बिजली का बिल भर रहा है और अपनी रोजीरोटी उसी कारोबार से चला रहा है, तो अचानक उसके सामने सीलबंदी का खतरा खड़ा हो जाए तो उसका सवाल स्वाभाविक है आखिर गलती किसकी है? व्यवस्था की यह जिम्मेदारी थी कि वह समय रहते यह तय करती कि कौनसा क्षेत्र आवासीय रहेगा, कहां व्यावसायिक गतिविधियां होंगी और कहां मिश्रित भूमि उपयोग की अनुमति होगी। यदि प्रशासन ने वर्षों तक स्थिति को स्वीकार किया और अब अचानक कठोर कार्रवाई शुरू कर दी, तो इसका सबसे बड़ा असर छोटे और मध्यम व्यापारियों पर पड़ेगा। कमलनाथ के पक्ष में खड़े राजनीतिक तर्क का एक महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि शहर नियोजन में केवल नियम लागू करना पर्याप्त नहीं होता। नियमों को शहर की वास्तविक जरूरतों के साथ जोड़ना पड़ता है। यही व्यावहारिक शहरी नियोजन की पहचान है।

भोपाल को चाहिए व्यावहारिक मास्टर प्लान

आज जरूरत ऐसे मास्टर प्लान की है जो भोपाल की मौजूदा वास्तविकता को स्वीकार करे। दिल्ली और देश के दूसरे बड़े शहरों की तरह भोपाल में भी मिश्रित भूमि उपयोग यानी मिक्स्ड लैंड यूज जैसे विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है। जहां कोई क्षेत्र वर्षों से व्यावसायिक केंद्र बन चुका है, वहां केवल दुकानों को हटाना समस्या का समाधान नहीं है। इसके बजाय वहां पार्किंग की व्यवस्था की जाए, यातायात का प्रबंधन सुधारा जाए, पैदल चलने वालों के लिए बेहतर स्थान बनाए जाएं, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ते सुनिश्चित किए जाएं और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाए। शहर को व्यवस्थित करने का मतलब शहर की आर्थिक गतिविधियों को खत्म करना नहीं हो सकता।

सम्पादकीय

ब्रिक्स सम्मेलन की भारत को मेजबानी

ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी भारत को मिलना केवल एक अंतरराष्ट्रीय आयोजन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि वैश्विक कूटनीति के बदलते स्वरूप में भारत की बढ़ती भूमिका का महत्वपूर्ण संकेत है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ हुआ ब्रिक्स आज विस्तारित होकर विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों के एक बड़े समूह का मंच बन चुका है। ऐसे समय में जब विश्व व्यवस्था अनेक राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक चुनौतियों से गुजर रही है, भारत के पास ब्रिक्स की मेजबानी के माध्यम से वैश्विक दक्षिण की आवाज को अधिक प्रभावी ढंग से सामने रखने का अवसर है। भारत के लिए यह अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। एक ओर पश्चिमी देशों का प्रभाव कायम है, तो दूसरी ओर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की अर्थव्यवस्थाएं अपनी सामर्थ्य के साथ वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में अधिक हिस्सेदारी चाहती हैं। ब्रिक्स इसी आकांक्षा का प्रतिनिधि मंच बनकर उभरा है। भारत की मेजबानी इस मंच को केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित रखने के बजाय विकास, तकनीक, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में सुधार जैसे व्यापक विषयों से जोड़ सकती है।

भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी संतुलित विदेश नीति रही है। रूस के साथ ऐतिहासिक संबंध, अमेरिका और यूरोप के साथ बढ़ते रणनीतिक सहयोग तथा चीन के साथ जटिल संबंधों के बीच भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए स्वतंत्र कूटनीतिक पहचान कायम रखी है। ब्रिक्स की मेजबानी के दौरान यही संतुलन भारत की सबसे बड़ी परीक्षा भी होगा। विशेषकर भारत-चीन संबंधों की संवेदनशीलता को देखते हुए सम्मेलन में आर्थिक सहयोग और राजनीतिक मतभेदों के बीच संतुलन साधना आसान नहीं होगा। ब्रिक्स का विस्तार इस मंच की संभावनाओं के साथ-साथ उसकी चुनौतियां भी बढ़ाता है। नए सदस्य देशों के जुड़ने से संगठन का भौगोलिक और आर्थिक प्रभाव बढ़ा है, लेकिन सदस्य देशों के हितों में विविधता भी आई है। ऐसे में भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि ब्रिक्स किसी एक देश के प्रभाव का मंच न बनकर सामूहिक हितों का मंच बने।

भारत की अध्यक्षता का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि वह सदस्य देशों के बीच संवाद और सहमति की कितनी मजबूत जमीन तैयार कर पाता है।

विकासशील देशों के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता भी ब्रिक्स के एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व और निर्णय क्षमता को बढ़ाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। भारत इस मुद्दे को नई दिशा दे सकता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे संस्थानों को अधिक प्रभावी बनाना, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देना और विकास परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था तैयार करना ब्रिक्स की उपयोगिता को और बढ़ा सकता है। तकनीक का क्षेत्र भी भारत के लिए अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, फिनटेक और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय अनुभव अर्जित किया है। इन अनुभवों को ब्रिक्स देशों के साथ साझा कर भारत विकासशील दुनिया के लिए एक व्यावहारिक मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही ऊर्जा सुरक्षा, हरित ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर भी साझा रणनीति की आवश्यकता है।

भारत को इस सम्मेलन को भव्य आयोजन से आगे ले जाकर ठोस परिणामों का मंच बनाना होगा। घोषणाओं और संकल्पों की लंबी सूची से अधिक महत्वपूर्ण यह होगा कि सम्मेलन के बाद सहयोग की ऐसी परियोजनाएं सामने आएं, जिनका प्रभाव आम नागरिकों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं तक दिखाई दे। ब्रिक्स की मेजबानी भारत की कूटनीतिक प्रतिष्ठा का अवसर है, लेकिन उससे भी अधिक यह जिम्मेदारी है। यदि भारत आर्थिक सहयोग, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं और बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के मुद्दों पर सदस्य देशों को साथ लाने में सफल होता है, तो यह सम्मेलन भारत की विदेश नीति के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन सकता है। दुनिया आज भारत को केवल एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि समाधान प्रस्तुत करने वाली शक्ति के रूप में देखना चाहती है। ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी भारत को इसी अपेक्षा को सार्थक करने का अवसर प्रदान करती है।

सियासी गहमागहमी

सागर में बिक रही जहरीली शराब का जिम्मेदार आरोपी कौन?

सागर में जहरीली शराब की बिक्री का मामला केवल अवैध कारोबार का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक व्यवस्था की जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। यदि कुछ लोग चोरी-छिपे जहरीली शराब बनाकर बेच रहे हैं तो वे निश्चित रूप से कानून के कठघरे में खड़े किए जाने चाहिए, लेकिन सवाल यह भी है कि यह कारोबार लंबे समय तक चलता कैसे रहा? क्या जिम्मेदार विभागों को इसकी भनक नहीं लगी या फिर निगरानी व्यवस्था कहीं न कहीं विफल रही? अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर कार्रवाई होना जरूरी है, लेकिन कार्रवाई का अर्थ केवल कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह भी जांच का विषय होना चाहिए कि शराब बनाने के लिए सामग्री कहां से आई, उसका वितरण नेटवर्क कितना बड़ा था और संबंधित क्षेत्रों में निगरानी करने वाली एजेंसियां क्या कर रही थीं। हर घटना के बाद कुछ लोगों को आरोपी बताकर मामला बंद कर देना आसान है, लेकिन असली सवाल व्यवस्था की जवाबदेही का है। यदि प्रशासन को समय रहते जानकारी थी और कार्रवाई नहीं हुई, तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए; और यदि जानकारी ही नहीं थी, तो यह खुफिया एवं निगरानी तंत्र की गंभीर कमजोरी है। जहरीली शराब किसी एक व्यक्ति की जिंदगी नहीं छीनती, बल्कि पूरे परिवार को तबाह कर देती है। इसलिए सागर की घटना में केवल आरोपी नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही की संभावनाओं की भी निष्पक्ष जांच जरूरी है। जनता को यह जवाब मिलना ही चाहिए।

मप्रः क्या प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच नहीं बैठ रहा तालमेल?

मध्यप्रदेश भाजपा की राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बीच तालमेल को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजनीतिक गलियारों में उठ रहे सवालों को महज अटकल कहकर खारिज किया जा सकता है, लेकिन संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय किसी भी राजनीतिक दल की सफलता के लिए अनिवार्य है। ऐसे में दोनों नेताओं की कार्यशैली और निर्णयों को लेकर होने वाली चर्चाएं स्वाभाविक रूप से राजनीतिक नजरों को आकर्षित करती हैं। मुख्यमंत्री सरकार की नीतियों और प्रशासनिक फैसलों का नेतृत्व करते हैं, जबकि प्रदेश अध्यक्ष की प्राथमिक जिम्मेदारी संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना है। दोनों भूमिकाएं अलग होने के बावजूद इनके बीच संवाद और सामंजस्य बेहद जरूरी है। यदि कहीं मतभेद हैं तो उनका समाधान सार्वजनिक चर्चा के बजाय संगठनात्मक स्तर पर होना चाहिए। भाजपा जैसी अनुशासित पार्टी में व्यक्तिगत समीकरणों से अधिक महत्व संगठनात्मक मर्यादा और सामूहिक नेतृत्व का होता है। इसलिए असली सवाल यह नहीं कि दोनों नेताओं के बीच मतभेद हैं या नहीं, बल्कि यह है कि सरकार और संगठन मिलकर जनता और कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं को कितनी प्रभावी ढंग से पूरा कर रहे हैं। फिलहाल तालमेल को लेकर उठ रही चर्चाओं पर अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। आने वाला समय ही बताएगा कि यह केवल राजनीतिक अटकल है या वास्तव में सरकार और संगठन के बीच किसी बेहतर समन्वय की जरूरत महसूस की जा रही है।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

भारत की शिक्षा प्रणाली उसी पीढ़ी को विफल कर रही है जिसे ऊंचा उठाने के लिए बनाई गई थी।
पेपर लीक। भारी फीस। जर्जर बुनियादी ढांचा। लाखों युवा भारतीय ईमानदारी से मेहनत करते हैं, और प्रणाली फिर भी उन्हें निराश करती है।
इसे ठीक करने की शुरुआत उन लोगों की सुनकर होती है जो इसके असफलताओं को रोज झेलते हैं।

-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 30 से अधिक नागरिकों की मौत होने के बाद अब यह तथ्य सामने आया है कि प्रदेश में 1766 स्थानों पर शराब का अवैध कारोबार हो रहा है। यह रिपोर्ट किसी स्वतंत्र संस्था की नहीं बल्कि सरकार के आबकारी विभाग की है, जिसकी जिम्मेदारी शराब के व्यापार के नियमन और अवैध शराब पर पाबंदी लगाने की है।

-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

छात्र राजनीति से कांग्रेस पार्टी का प्रमुख चेहरा बने रणदीप सिंह सुरजेवाला

समता पाठक/जगत प्रवाह

रणदीप सिंह सुरजेवाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने छात्र राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक अपनी अलग पहचान बनाई है। कानून की पढ़ाई प्रभावी वक्तृत्व.कौशल और संगठनात्मक क्षमता उनके राजनीतिक व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। वर्तमान में वे राज्यसभा सांसद हैं तथा कांग्रेस के महासचिव के रूप में संगठनात्मक जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। कांग्रेस की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वे कर्नाटक और गुजरात के प्रभारी भी हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला का जन्म 03 जून 1967 को हुआ। उनके पिता चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला हरियाणा की राजनीति के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री रहे हैं। राजनीतिक परिवेश में पले.बढ़े रणदीप सिंह ने बहुत कम उम्र में ही सार्वजनिक जीवन की बारीकियों को समझना शुरू कर दिया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नरवाना में हुई और आगे की पढ़ाई चंडीगढ़ में हुई। उन्होंने बीण्कॉमण् ऑनर्सए एलएलण्बीण् तथा राजनीति विज्ञान में एमण्एण् की शिक्षा प्राप्त की। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वकालत को अपना पेशा बनाया। वर्ष 1988 में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होकर उन्होंने दिल्ली में वकालत शुरू की और बाद में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में भी प्रैक्टिस की। कानून के क्षेत्र में रहते हुए किसानोंए भूमि.अधिकार और सामाजिक न्याय से जुड़े विषयों पर उनका जुड़ाव बना रहा। विश्वविद्यालय जीवन में भी उनकी सक्रियता उल्लेखनीय रही। वे पंजाब विश्वविद्यालय के सीनेटर और विभिन्न अकादमिक निकायों के सदस्य रहे।

राजनीतिक जीवन में उनका प्रवेश युवा कांग्रेस के माध्यम से हुआ। संगठन में विभिन्न दायित्व निभाते हुए वे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के युवा चेहरों में उभरे। वर्ष 2000 से 2005 तक उन्होंने भारतीय युवा कांग्रेस का नेतृत्व किया। हरियाणा की राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका और संगठनात्मक क्षमता ने उन्हें कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं की पंक्ति में ला खड़ा किया। सुरजेवाला के राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव वर्ष 2005 रहाए जब उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में नरवाना सीट से तत्कालीन मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला को पराजित किया। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार में उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला। उन्होंने परिवहनए नागरिक उड्डयनए लोक निर्माणए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकीए बिजलीए संसदीय कार्य तथा उद्योग एवं वाणिज्य जैसे विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 2009 में वे कैथल से विधानसभा पहुंचे और बाद में भी प्रदेश सरकार में मंत्री रहे।

राज्य की राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़ते हुए सुरजेवाला कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ताओं में शामिल हुए। संसद में भी वे किसानोंए कृषिए शिक्षाए महंगाईए सामाजिक न्याय और विभिन्न जनहित के मुद्दों को उठाते रहे हैं। राज्यसभा के आधिकारिक अभिलेखों में उनके द्वारा कृषिए शिक्षा और वायु प्रदूषण जैसे विषयों पर प्रश्न एवं हस्तक्षेप दर्ज हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला का राजनीतिक व्यक्तित्व मूलतः संवादए तर्क और संगठन के त्रिकोण पर आधारित दिखाई देता है। वे कांग्रेस की ओर से सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस में मुखर भूमिका निभाते रहे हैं। उनकी भाषण शैली में आंकड़ोंए राजनीतिक तर्कों और तीखे प्रतिपक्षी तेवरों का मिश्रण देखने को मिलता है। चार दशकों के सार्वजनिक जीवन में उन्होंने हरियाणा की क्षेत्रीय राजनीति से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की रणनीति और संचार व्यवस्था तक अपनी भूमिका बनाई है। वर्तमान में कांग्रेस संगठन में महासचिव और राज्यसभा सांसद के रूप में उनकी सक्रियता उनके राजनीतिक सफर के राष्ट्रीय चरण को रेखांकित करती है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की श्री महालक्ष्मी अष्टभुजा मंदिर में पूजा-अर्चना

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद नैनीताल भ्रमण के दौरान बरेली रोड स्थित श्री महालक्ष्मी अष्टभुजा मंदिर, बेरीपड़ाव में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री ने माँ महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर प्रदेश एवं देशवासियों की सुख-शांति, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। उन्होंने प्रदेश की निरंतर प्रगति और जनकल्याण के लिए भी प्रार्थना की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, सांसद अजय भट्ट, अनिल बलूनी, कैबिनेट मंत्री रामसिंह कैड़ा,विधायक डॉ. मोहन सिंह बिष्ट सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं श्रद्धालु उपस्थित थे।

तिघरा बांध के खुले गेट, नजारा देखने महापौर सहित बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे

-संतोष सिंह कुशवाह

जगत प्रवाह. ग्वालियर। ग्वालियर की लाइफलाइन तिघरा जलाशय लबालब हो गया है। अंततः बांध का जलस्तर 739.50 फीट के उपर पहुंचते ही शुक्रवार सायं 6 बजे बाद जलसंसाधन विभाग के कारिंदों ने तीन गेटों को 9-9 इंच खोलकर 1040 क्यूसेक अतिरिक्त जल की निकासी सांक नदी में की गई। उल्लेखनीय है कि तिघरा बांध की क्षमता 740 फीट है। बांध पुराना होने के कारण इसे सुरक्षा की दृष्टि से 739 फीट तक ही भरा जाता है। इससे ज्यादा पानी होने पर फिर गेट खोलकर अतिरिक्त पानी निकाला जाता है। लगातार पानी की आवक के चलते शुक्रवार को तिघरा बांध का जलस्तर 739.50 फीट के पार पहुंच गया। इसके बाद देर सायं तिघरा के गेट खोले गये। हालांकि अभी कुछ दिन पहले तक तिघरा पानी के लिये संघर्ष कर रहा था। लेकिन अच्छी बारिश के चलते तिघरा बांध अब लबालब हो गया है। तिघरा के लबालब होने की खबर व सुहावना मौसम होने से बड़ी संख्या में सैलानी तिघरा पहुंच गये और गेटों से पानी की निकासी का अदभुत नजारा अपने कैमरों में कैद कर आनंद लिया। तिघरा बांध के गेटों को महापौर श्रीमती शोभा सतीश सिकरवार की मौजूदगी में खोला गया।

तिघरा बांध के गेट खोलने से पहले जलसंसाधन विभाग ने सांक नदी के किनारे बसे हुए गांव सहित ग्वालियर के प्रभावित क्षेत्र ग्राम तिघरा, ग्राम कैथा, ग्राम तालपुरा, ग्राम महिदपुर, ग्राम पृथ्वीपुर, ग्राम कुलैथ, ग्राम अगरा भटपुरा, ग्राम दुगनावली व ग्राम तिलघना और जिला मुरैना के प्रभावित क्षेत्र ग्राम पहाड़ी, ग्राम जखौदा, व ग्राम बामोर के लोगों को सतर्क रहने व नदी किनारे न जाने हेतु सूचित किया। तिघरा जलाशय का अतिरिक्त पानी सांक नदी में छोड़ा गया। यह पानी सांक नदी से होते हुए पिलौआ बांध में पहुँचेगा।

14 सितंबर हिंदी दिवस पर विशेष

सरल हिंदी की बढ़ती वैश्विक व्यापकता

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

हिंदी को लेकर अकसर शिकायत रहती है कि यह भाषा सरल नहीं है, इसलिए किशोर एवं युवा वर्ग इससे दूर हो रहा है। जबकि यह सच्चाई नहीं है। देश भर में आजीविका और बोलचाल की भाषा बन जाने के कारण पूरे देश में हिंदी का बोलबाला और सर्व-स्वीकार्यता बढ़ रही है। स्वतंत्रता आंदोलन, हिंदी फिल्में, टीवी सीरियल, विज्ञापन और अब डिजिटल और सोशल मीडिया की प्रमुख भाषा हिंदी ही है। इन माध्यमों पर हिंदी की लोक बोली और भाषाओं का प्रभुत्व निरंतर बढ़ रहा है। 'हनुमान अंश' फिल्म के लोकप्रिय होने का कारण इसके लोकगीत और आंचलिक भाशा ही है। सरकारी काम-काज में हिंदी की उपयोगिता बढ़ाने की दृष्टि से केंद्रीय राजभाषा मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी करके हिंदी अनुवाद की जटिलता को दूर करने का काम भी कर दिया है। शासकीय विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने पत्रों व अपने अभिलेखों में उर्दु, अंग्रेजी, अरबी, फारसी और तुर्की मूल के उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जो लोकप्रिय होने के साथ प्रचलन में है। अतएव अनुवादित हिंदी में अब 'लोह पथ गामिनी' और 'द्विचक्र वाहिनी' जैसे दुरूह शब्दों की अनिवार्यता खत्म हो गई है।

वैसे भी भाषा केवल विचारों को व्यक्त करने का माध्यम नहीं है, वह मनुष्य के अनुभवों, संवेदनाओं, स्मृतियों और सपनों को एक-दूसरे तक पहुँचाने वाला सेतु भी है। कोई भाषा तभी जीवंत और प्रभावशाली बनती है, जब वह अपने समय के मनुष्य से सहज संवाद कर सके। हिंदी के संदर्भ में आज आवश्यकता ऐसी भाषा की है जो न तो अनावश्यक रूप से कठिन हो और न ही अपनी अभिव्यक्ति की गरिमा खोए। वह सरल, सरस, संवेदनशील भी हो और समावेशी भी। इसी दृष्टि से 'सुवार्तित हिंदी' की संकल्पना महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। 'सुवारित' या 'सुवार्तित' को यदि हम व्यापक अर्थ में ग्रहण करें तो इसका आशय ऐसी हिंदी से हो सकता है जो अपने कथ्य को सुंदर, स्पष्ट, सहज और प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करे। ऐसी हिंदी पाठक पर शब्दों का बोझ नहीं डालती, बल्कि विचार और भाव को उसके मन तक स्वाभाविक रूप से पहुँचाती है। इसमें भाषा का सौंदर्य शब्दों की कठिनता में नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की सजीवता में दिखाई देता है।

सरलता का अर्थ भाषा को कमजोर या साधारण बना देना नहीं है। सरल भाषा वह है जिसमें जटिल विचारों को भी सहज ढंग से व्यक्त करने की क्षमता हो। विज्ञान, दर्शन, इतिहास, समाजशास्त्र अथवा साहित्य जैसे गंभीर विषय भी यदि सरल भाषा में प्रस्तुत किए जाएँ तो उनका प्रभाव व्यापक हो जाता है। हिंदी की शक्ति उसकी व्यापक जन संस्कृति में है। गांव से लेकर महानगर तक, विद्यार्थी से लेकर सामान्य पाठक तक और साहित्य से लेकर पत्रकारिता तक हिंदी के अनेक रूप दिखाई देते हैं। इसलिए हिंदी को केवल विद्वानों की भाषा न होकर सामान्य जन की अनुभूति और समझ की भाषा है।

किसी भी भाषा में एक ही बात को दो प्रकार से कहा जा सकता है। पहला वाक्य वह जो केवल सूचना देता है, जबकि दूसरा वाक्य उसी सूचना में अनुभूति और जीवन को संवेदित चेतना से जोड़ देता है। सरस हिंदी पाठक के मन में दृश्य बनाती है, संवेदना जगाती है और उसे विषय से जोडती है। इसलिए हिंदी की मूल प्रकृति समावेशी है। भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता बहुत व्यापक है। हिंदी अनेक भारतीय भाषाओं से शब्द ग्रहण करती रही है और अपने विकास के क्रम में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं से प्रभावित हुई है। इसलिए हिंदी को किसी एक संकीर्ण भाषाई सीमा में नहीं बांधा जा सकता है।

हिंदी के इस समावेशी स्वरूप को सामने लाने का काम भारतेंदु युग में ही आरंभ हो गया था। यद्यपि आरंभ में हिंदी गद्य अपरिमार्जित और अशुद्ध भी था। इस कमी पर महावीर प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि गई और उन्होंने अनेक समस्याओं से जूझते हुए भाषा को परिस्कृत करने का काम किया। इस समय हिंदी के कई रूप थे- पूर्वी बोली, ब्रज, अवधी और बुंदेलखंडी द्विवेदी जी ने इसे एकरूप में ढालने का काम 'सरस्वती' पत्रिका के माध्यम से किया। हालांकि हिंदी की खड़ी बोली का स्वरूप दसवीं से चैदहवीं षताब्दी के बीच विकसित होना आरंभ हो गया था, परंतु 19वीं षताब्दी में पहुंचने पर ही आधुनिक मानक हिंदी खड़ी बोली के रूप में स्थापित हो पाई। इसका उपन्यास, कहानी और नाटकों को गद्य रूप देने का काम मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' और महादेवी वर्मा ने प्रमुख रूप से किया। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में जीवन को व्यावहारिक यथार्थवाद से जोड़ा। प्रसाद ने अपने उपन्यास, कहानी, नाटक और निबंधों में भाशा की ऐतिहासिक चेतना को स्थान दिया। निराला ने मजदूर वर्ग की समस्याओं को 'कुकुरमुत्ता' और 'वह तोड़ती पत्थर' जैसी आंदोलित करने वाली शब्द संरचना दी। महादेवी ने अपनी कविताओं में नारी सशक्तिकरण को भावुक व्यंजनाओं के साथ प्रस्तुत किया। महादेवी ने 'असीम' और 'ससीम' संबोधनों के माध्यमों से रहस्यवाद की उस दार्शनिक अवधारणा को अभिव्यक्त किया जो जीवात्मा और परमात्मा के अंतरसंबंधों को दर्शाती है।

रीतिकाल और छायावाद को लेकर अक्सर 'संस्कृतनिष्ट हिंदी' और 'सरल हिंदी' के बीच विवाद खडा कर दिया जाता है। वास्तव में शुद्धता और सरलता एक-दूसरे की विरोधी नहीं हैं। भाषा में व्याकरण, वर्तनी और अर्थ की स्पष्टता आवश्यक है। अतएव इसे आलोचकों का दृष्टिदोष या पूर्वग्रह ही कहा जाएगा कि जिस छायावादी युग का छायावादी साहित्य हिंदी में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, उसकी आलोचना इसलिए हुई, क्योंकि यही वह साहित्य है, जिसमें इतिहास के पुन्र्लेखन के साथ भारतीय ज्ञान-परंपरा की सशक्त अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। हिंदी के साहित्यिक लेखन का उद्देश्य केवल साहित्य की प्रवृत्तियों का अनुसरण नहीं होना चाहिए, अपितु भाषाई शब्द व्यंजना और शिल्प को संवाद-संप्रेषणीयता के परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। संप्रेषणीयता ही रचना की वह शक्ति है, जो भाषा को सुवारित और सहज बनाती है। इसी कारण सोषल मीडिया में यह भाशा भी डिजिटल रूप में खूब स्वीकार की जा रही है।

नरेंद्र मोदी देश के ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री हैं, जो हिंदी में एशिया समेत यूरोपीय देशों में बेहिचक भाषण देते हैं। मोदी दक्षेश नेताओं से हिंदी में द्विपक्षीय वार्ताएं करके और संयुक्त राष्ट्र संघ समेत दुनिया के अनेक देशों में हिंदी में दिए उद्बोधनों में तालियां बटोरकर दुनिया को जता चुके हैं कि विश्व में हिंदी को बोलने और समझने वालों की संख्या करोड़ों में है। मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने जिस भाषा में वोट मांगे, उसी भाषा को देश-विदेश में संवाद की भाषा बनाए हुए हैं। इसी कारण योग दिवस को संयुक्त राष्ट्र में मान्यता मिली है। अतएव इस सुवारित हिंदी के जल्दी ही संयुक्त राष्ट्र की भाषा बन जाने की उम्मीद की जाने लगी है।

1945 में संरा की आधिकारिक भाषाएं 4 थीं, अंग्रेजी, रशियन, फ्रांसीसी और चीनी। ये भाषाएं अपनी विलक्षण या ज्यादा बोली जाने के बनिस्बत, संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं इसलिए बन पाई थीं, क्योंकि ये विजेता महाशक्तियों की भाषाएँ थीं। बाद में इनमें अरबी और स्पेनिश शामिल कर ली गईं। विश्व-पटल पर हिंदी बोलने वालों की संख्या दूसरे स्थान पर है। यही नहीं, भारतीय और अनिवासी भारतीयों को जोड़ दिया जाए तो हिंदी पहले स्थान पर आकर खड़ी हो जाती है। भाषाई आंकड़ों की दृष्टि से जो सर्वाधिक प्रामाणिक जानकारियां सामने आई हैं, उनके आधार पर संयुक्त राश्ट्र की छह आधिकारिक भाषाओं की तुलना में हिंदी बोलने वालों की स्थिति निम्न है, मंदारिन 80 करोड़, हिंदी 55 करोड़, स्पेनिश 40 करोड़, आंग्रेजी 40 करोड़, अरबी 20 करोड़, रूसी 17 करोड़ और फ्रेंच 9 करोड़ लोग बोलते हैं। स्पश्ट है है, हिंदी संरा की अग्रिम पंक्ति में खड़ी होने का वैध अधिकार रखती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की 43.63 प्रतिशत आबादी हिंदी बोलती हैं। यदि इसमें भोजपुरी, ब्रज, अवधि, बघेली, बुंदेली और हिंदी से मिलती अन्य भाषाएं भी जोड़ दी जाएं तो इस संख्या में 13.9 करोड़ लोग और जुड़ जाएंगे और यह प्रतिशत बढ़कर 54.63 हो जाएगा। हिंदी का यह विश्व व्यापी विस्तार इसकी सहज सरलता से ही संभव हुआ है।

ट्रांसपोर्ट नगर में GDA अध्यक्ष ने किया EWS भवनों का निरीक्षण

-संतोष सिंह कुशवाह

जगत प्रवाह. ग्वालियर। ग्वालियर विकास प्राधिकरण (GDA) के अध्यक्ष मधुसूदन भदौरिया ने प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आवासीय निर्मित EWS भवनों सहित विभिन्न संपत्तियों का निरीक्षण कर उनकी वर्तमान स्थिति तथा नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में व्याप्त मूलभूत समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निराकरण किया जाए और नागरिकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। भदौरिया ने विक्रय योग्य प्राधिकरण की संपत्तियों को

चिन्हित कर उनके शीघ्र विक्रय की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान GDA अध्यक्ष ने आनंद नगर स्थित पोस्ट ऑफिस के लिए आरक्षित भूमि का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान संपदा अधिकारी विकास भदौरिया, सहायक यंत्री सत्येंद्र तोमर, सहायक यंत्री मनोज माथुर सहित प्राधिकरण के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रो. डीएस राजपूत ने संभाला जीवाजी विश्वविद्यालय कुलगुरु का पदभार

-संतोष सिंह कुशवाह

जगत प्रवाह. ग्वालियर। जीवाजी विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलगुरु प्रो. डीएस राजपूत ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शोध को बढ़ावा देने, रोजगारमूलक पाठ्यक्रम शुरू करने और विद्यार्थियों के लिए बेहतर अकादमिक वातावरण तैयार करने को अपनी प्राथमिकता बताया। प्रो. राजपूत ने कहा कि विद्यार्थियों को अध्ययन एवं शोध के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए देश-विदेश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों के साथ अनुबंध किए जाएंगे। इन करारों का उद्देश्य केवल संस्थागत संबंध बनाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को दूसरे विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में जाकर अध्ययन, शोध तथा नई तकनीकों को समझने का अवसर देना होगा। इससे जीवाजी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक पहचान भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि बदलते

समय और रोजगार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों को डिग्री के साथ रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। शोध गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नए शोध केन्द्र स्थापित करने की भी तैयारी है। विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों के संबंध में उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर चर्चा कर पदों को भरने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पर्याप्त शिक्षकों के बिना शिक्षण और शोध कार्य को गति देना कठिन है।

गणेश चतुर्थी पर विशेष

श्रीगणेश से सीखिये- सुनना, चुनना, बदलना और आगे बढ़ना

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

गणेश चतुर्थी पर हम भगवान श्री गणेश से सुख, समृद्धि, बुद्धि और विघ्नों से मुक्ति का आशीर्वाद माँगते हैं लेकिन इस बार एक प्रश्न स्वयं से भी पूछिए, जिस विघ्नहर्ता को हम अपने जीवन की बाधाएँ दूर करने के लिए पूजते हैं, क्या हमने कभी यह समझने की कोशिश की कि उनका स्वरूप हमें स्वयं बाधाओं से निपटने की कितनी बड़ी कला सिखाता है? श्री गणेश केवल आराधना के देवता नहीं, जीवन-प्रबंधन की अद्भुत प्रेरणा भी हैं। उनका स्वरूप मानो कहता है कि जीवन में हर समस्या के समाधान के लिए चमत्कार की प्रतीक्षा मत कीजिए, अपने भीतर सही गुण विकसित कीजिए। संयोग से पर्व है चतुर्थी का, इसलिए इस गणेश चतुर्थी पर विघ्नहर्ता से जीवन के चार सूत्र लेते हैं। ये चार वरदान ऐसे हैं, जिन्हें माँगना नहीं, अपनाना है।

पहला सूत्र- शोर के युग में 'सुनना' सीखिए

गणेशजी के विशाल कान हमें सबसे पहली और आज शायद सबसे जरूरी सीख देते हैं- बोलने से पहले सुनिए। आज हमारे पास अभिव्यक्ति के जितने साधन हैं, शायद सुनने का धैर्य उतना ही कम हुआ है। सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति कुछ कहना चाहता है, कार्यस्थल पर अपनी बात मनवाना चाहता है और रिश्तों में भी कई बार हम सामने वाले को समझने के बजाय उत्तर देने के लिए सुनते हैं। यहीं गणेशजी का पहला सूत्र काम आता है- जो ज्यादा सुनता है, वह ज्यादा समझता है; और जो ज्यादा समझता है, उसके निर्णय बेहतर होते हैं। युवा हों, अधिकारी, उद्यमी या परिवार के मुखिया - अच्छा श्रोता होना कमजोरी नहीं, नेतृत्व की ताकत है। कई रिश्ते एक सही शब्द से नहीं, कुछ मिनट चुपचाप सुन लेने से बच जाते हैं।

दूसरा सूत्र- हर सूचना नहीं, सही सूचना चुनिए

गणेशजी की छोटी और सजग आँखें तथा विलक्षण बुद्धि दूसरी सीख देती हैं- दुनिया कितनी दिख रही है, इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि उसमें से आप देख क्या रहे हैं। हम सूचना की कमी के नहीं, सूचना की अधिकता के दौर में जी रहे हैं। मोबाइल की एक स्क्रीन पर समाचार, रील्स, राय, सलाह और तुलना- सब एक साथ मौजूद हैं। आज की चुनौती ज्ञान प्राप्त करना नहीं, उपयोगी और अनुपयोगी के बीच चयन करना है। युवा पीढ़ी के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हर ट्रेंड आपका रास्ता नहीं है, हर वायरल विचार सत्य नहीं है और हर दूसरे व्यक्ति की सफलता आपके जीवन का पैमाना नहीं हो सकती। गणेशजी बुद्धि के साथ विवेक की प्रेरणा देते हैं। बुद्धि बताती है कि क्या किया जा सकता है; विवेक बताता है कि क्या किया जाना चाहिए। जीवन की दिशा अक्सर इसी छोटे-से अंतर से तय होती है।

तीसरा सूत्र- परिस्थिति बदले तो तरीका बदलने से मत डरिए

गणेशजी की सूँड उनके स्वरूप का अत्यंत रोचक प्रतीक है। उसमें विशाल वृक्ष को हिलाने की शक्ति भी है और अत्यंत छोटी वस्तु को उठाने की संवेदनशीलता भी। यही तीसरा सूत्र है- सामर्थ्यवान बनिए, लेकिन उससे भी ज्यादा अनुकूलनशील बनिए। आज नौकरी, कारोबार, तकनीक और कौशल तेजी से बदल रहे हैं। जो व्यक्ति केवल एक पुराने तरीके से चिपका रहेगा, उसके लिए परिवर्तन विघ्न बन जाएगा लेकिन जो सीखने, बदलने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने के लिए तैयार है, वही परिवर्तन को अवसर बना सकता है। हर समस्या को ताकत से नहीं सुलझाया जाता। कहीं दृढ़ता चाहिए, कहीं विनम्रता; कहीं तेजी, कहीं धैर्य। परिस्थिति के अनुसार अपनी क्षमता का सही उपयोग ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। गणेशजी हमें कठोर नहीं, सक्षम और लचीला बनने की प्रेरणा देते हैं।

चौथा सूत्र- अपूर्णता को बहाना नहीं, अपनी पहचान बनाइए

गणेशजी का एकदंत स्वरूप शायद आधुनिक जीवन के लिए सबसे खूबसूरत संदेश देता है -पूर्ण होने की प्रतीक्षा में महत्वपूर्ण काम मत रोकिए। आज बहुत से लोग शुरुआत इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि सही समय नहीं आया, पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, आत्मविश्वास पूरा नहीं है या परिस्थितियाँ मनमाफिक नहीं हैं। लेकिन जीवन कभी पूरी तरह अनुकूल होकर हमारे सामने नहीं आता। गणेशजी का एकदंत स्वरूप हमें याद दिलाता है कि कमी आपकी क्षमता का अंतिम निर्णय नहीं करती। जो उपलब्ध है, उससे श्रेष्ठ करना ही पुरुषार्थ है। असफलता आई है तो उससे सीखिए, योजना टूटी है तो नई बनाइए, रास्ता बंद है तो दूसरा खोजिए। जीवन की सार्थकता इस बात में नहीं कि हमें कितने कम विघ्न मिले, बल्कि इसमें है कि विघ्नों के बाद भी हम कितनी दूर चले।

यही कारण है कि श्री गणेश को किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में स्मरण किया जाता है। शायद संदेश यही है कि शुभ शुरुआत का अर्थ बाधाओं से मुक्त रास्ता नहीं, बल्कि बाधाओं से बड़ा संकल्प है। इस गणेश चतुर्थी पर हम घर, ऑफिस और मंदिर में गणपति की आराधना करें, लेकिन उनके चार सूत्र अपने भीतर भी स्थापित करें, कानों में सुनने का धैर्य, दृष्टि में सही को चुनने का विवेक, स्वभाव में परिस्थितियों के अनुरूप बदलने की क्षमता और मन में अपनी अपूर्णताओं के बावजूद आगे बढ़ने का साहस।फिर शायद हमें हर बार विघ्नहर्ता से यह नहीं कहना पड़ेगा कि हमारे रास्ते के सारे विघ्न हटा दीजिए। हम यह भी कह सकेंगे- हे गणपति बप्पा, इतनी बुद्धि और सामर्थ्य दीजिए कि विघ्न आए तो हम स्वयं उससे बड़े हो जाएँ।

आप सभी को श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएँ। गणपति बप्पा मोरया

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

हिमालय पर्वत से छेड़खानी खतरनाक

नेपाल में बीते महीने आई बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। नेपाल और तिब्बत सीमा पर आई इस विनाशकारी बाढ़ की वजह ग्लेशियर टूटना माना जा रहा है। इस आपदा ने एक बार फिर हिमालय का अत्यंत संवेदनशील और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की अनदेखी पर सवाल उठना शुरू हो गया है। क्या हम बिना हिमालय के भारत की कल्पना कर सकते हैं। हिमालय केवल बर्फ से ढकी पर्वत-श्रृंखला नहीं है, बल्कि भारत की जलवायु, नदियों, जैव-विविधता, कृषि, संस्कृति और करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। उत्तर में विशाल प्रहरी की तरह खड़ा हिमालय भारत को प्राकृतिक सुरक्षा देने के साथ-साथ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी अनेक महत्वपूर्ण नदियों को जन्म देता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में विकास, पर्यटन, सड़क निर्माण, खनन, बांधों और अनियंत्रित शहरीकरण के नाम पर हिमालयी क्षेत्रों में जिस प्रकार मानवीय हस्तक्षेप बढ़ा है, वह गंभीर चिंता का विषय बन गया है। प्रकृति के इस अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र से लगातार छेड़खानी भविष्य में विनाशकारी परिणाम पैदा कर सकती है। हिमालय भू-गर्भीय दृष्टि से अपेक्षाकृत युवा पर्वत-श्रृंखला है। यहां की चट्टानें कई क्षेत्रों में कमजोर और अस्थिर हैं। इसलिए अत्यधिक खुदाई, पहाड़ों को काटकर सड़क बनाना, सुरंगों का निर्माण और बड़ी इमारतें खड़ी करना भू-स्खलन के खतरे को बढ़ा सकता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के हिमालयी राज्यों में बरसात के समय बार-बार होने वाले भूस्खलन हमें चेतावनी देते हैं कि पहाड़ों की अपनी प्राकृतिक सीमा होती है। यदि उस सीमा को नजरअंदाज किया जाए तो परिणाम केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि मानवीय त्रासदी के रूप में सामने आते हैं।

भारत के हिमालयी क्षेत्रों में विकास की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। वहां रहने वाले लोगों को अच्छी सड़कें, अस्पताल, शिक्षा, बिजली और रोजगार मिलना आवश्यक है। समस्या विकास से नहीं, बल्कि ऐसे विकास से है जिसमें क्षेत्र की भौगोलिक और पारिस्थितिक क्षमता को समझे बिना निर्माण किया जाए। कई स्थानों पर सड़क चौड़ी करने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाते हैं और पहाड़ों को विस्फोटकों से तोड़ा जाता है। यदि ढलानों को वैज्ञानिक तरीके से स्थिर न किया जाए तो यही सड़कें बाद में भूस्खलन और पत्थर गिरने के कारण लोगों के लिए खतरा बन सकती हैं।

अनियंत्रित पर्यटन भी हिमालय के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल, धर्मशाला और कई धार्मिक पर्यटन स्थलों पर हर वर्ष लाखों पर्यटक पहुंचते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है, लेकिन साथ ही पानी की मांग, यातायात, कचरा, प्लास्टिक और होटल निर्माण का दबाव भी बढ़ता है। कई शहरों की वहन क्षमता सीमित है, फिर भी वहां लगातार नए होटल और व्यावसायिक भवन बनते जा रहे हैं। यदि पर्यटन को पर्यावरण के अनुकूल नहीं बनाया गया तो हिमालयी शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और स्थिरता दोनों खो सकते हैं। जलविद्युत परियोजनाएं और बड़े बांध भी चर्चा का विषय हैं। हिमालयी नदियों से बिजली उत्पादन भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में योगदान कर सकता है, लेकिन हर नदी और हर घाटी में परियोजना बनाना उचित नहीं है। सुरंगों, बांधों और नदी के प्राकृतिक प्रवाह में परिवर्तन का प्रभाव स्थानीय पारिस्थितिकी, भूजल, मछलियों, जंगलों और आसपास की बस्तियों पर पड़ सकता है। इसलिए किसी भी परियोजना को मंजूरी देने से पहले स्वतंत्र और गंभीर पर्यावरणीय अध्ययन आवश्यक होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन ने हिमालय की समस्या को और गंभीर बना दिया है। बढ़ते तापमान के कारण कई हिमनदों में बदलाव देखा जा रहा है और हिमनदीय झीलों से जुड़े जोखिमों पर भी चिंता बढ़ी है। अत्यधिक वर्षा, बादल फटना और अचानक आने वाली बाढ़ जैसी घटनाएं हिमालयी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से विनाशकारी हो सकती हैं। यदि एक ओर प्रकृति जलवायु परिवर्तन के दबाव में है और दूसरी ओर मनुष्य जंगल काटकर तथा पहाड़ों को कमजोर करके अतिरिक्त दबाव डालता है, तो आपदाओं की तीव्रता और बढ़ सकती है।

हिमालय के जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं हैं। वे मिट्टी को बांधते हैं, वर्षा के पानी को नियंत्रित करते हैं, वन्यजीवों को आश्रय देते हैं और स्थानीय समुदायों की आजीविका का आधार हैं। इसलिए वनों की कटाई रोकना, स्थानीय प्रजातियों के वृक्ष लगाना और प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना आवश्यक है। निर्माण परियोजनाओं में स्थानीय समुदायों, वैज्ञानिकों, पर्यावरण विशेषज्ञों और भूवैज्ञानिकों की राय को वास्तविक महत्व दिया जाना चाहिए।

हमें यह समझना होगा कि पर्यावरण संरक्षण विकास का विरोध नहीं है। वास्तविक विकास वही है जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करे लेकिन आने वाली पीढ़ियों के जीवन और संसाधनों को खतरे में न डाले। हिमालयी क्षेत्रों के लिए छोटे और पर्यावरण-अनुकूल निर्माण, नियंत्रित पर्यटन, मजबूत आपदा प्रबंधन, वैज्ञानिक सड़क निर्माण, प्रभावी कचरा प्रबंधन और कठोर पर्यावरणीय नियमों की आवश्यकता है। हिमालय हमें बार-बार संकेत दे रहा है कि प्रकृति के साथ मनमानी की एक सीमा होती है। पर्वतों को केवल जमीन, खनिज, सड़क या पर्यटन स्थल के रूप में देखना बड़ी भूल होगी। हिमालय भारत की जीवनरेखा है। यदि हम उसकी रक्षा करेंगे तो वह हमारी नदियों, जंगलों, जलवायु और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करता रहेगा। लेकिन यदि विकास के नाम पर उससे लगातार छेड़खानी की गई, तो उसकी कीमत केवल पहाड़ों के लोगों को नहीं, बल्कि पूरे भारत को चुकानी पड़ सकती है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)